

हक एवं हिस्सा घोषित करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। प्रतिवादी सं. 1 को रकबा वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने के लिए वादीगण का सहयोग करने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी सं. 1 प्रथमतः टालमटोल के पश्चात 01.09.2015 को बमुकाम 8 टीके में इनकार हो गया व धमकी दी कि उपरोक्त रकबा किसी को हस्तान्तरण रहन व बैय आदि कर उपरोक्त रकबा से वादीगण को बेदख व वंचित करेगा। बाद पत्र वादीगण स्वीकार कर चक 8 टीके तहसील रायसिंहनगर का मु.नं. 11 के कि.नं. 22 में कि.नं. 23 के 0.076 है. कुल 0.228 है. बारांनी मु.नं. 48 प.नं. 185/307 के कि.नं. 1, 10, 20, 21, 22, 23/1 में कुल 1.581 है. नहरी मय खाला एवं मु.नं. 53 प.नं. 182/308 के कि.नं. 1, 5 एवं 6/1 में कुल 1.455 है. नहरी उपरोक्तानुसार कुल 3.264 है. नहरी बारांनी मय खाला (जमाबंदी संवत 2071-2074 के खाता सं. 103 अनुसार) एवं जमाबंदी खाता सं. 44 में दर्ज मु.नं. 51 की 186 हिस्सा यानि 9 बीघा 6 बिस्वा नहरी भूमि के प्रतिकूल कब्जाधारी होने के कारण उपरोक्त भूमि पर वादीगण का हक एवं हिस्सा घोषित कर खातेदार टिनेन्ट घोषित फरमाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 कि प्रति. सं. 1 स्वयं या उनका कोई हितबद्ध व्यक्ति या पश्चातवर्ती व्यक्ति किसी प्रकार की मदाखलत बेजा करने व उक्त रकबा को किसी प्रकार से किसी अन्य को हस्तान्तरण रहन व बैय आदि करने से बाज व ममनु रहे व पानी बारी में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करें व ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादीगण उपरोक्त रकबा से बेदखल व वंचित होते हो. पारित किये जाने की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। दिनांक 25.10.2016 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। जवाब सरकार पेश हुआ। प्रकरण में निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गयी-

1. आया कि विवादित की चक 8 टीके के मु.नं. 11, 48, 53 इस प्रकार कुल 3.264 है. विवादित भूमि पर सन 1992 से लगातार कब्जा है ? -वादी
2. आया कि वादीगण का उक्त विवादित भूमि पर सन 1956 से लगातार बुजुर्गों के मार्ग पर प्रतिकूल कब्जा एवं एडवर्स पोजेशन प्रतिवादी सं. 1 के ज्ञान अनुसार व इसकी मौन सहमति एवं स्वीकृति रही है। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 का हक एवं खातेदारी अधिकारी नहीं रह गये है, इसलिए लगातार वादीगण का कब्जा होने के कारण वादीगण उपरोक्त रकबा पर हक एवं हिस्सा घोषित करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने के अधिकारी है, इसी अनुसार हक एवं हिस्सा घोषित किया जाकर खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री वादीगण के पक्ष में पारित की जानी न्यायोचित है ? -वादी
3. आया कि वादीगण का सन 1992 से मामला पानी की पर्ची बाराबंदी व शुदगार गिरदावरी वादीगण के नाम होने से व भूमि धारक के रूप में प्रतिकूल कब्जा होने से विवादित भूमि का वादीगण का हक एवं हिस्सा घोषित कर खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जावे ? -वादी
4. यह घोषित किया जावे कि वादीगण के कब्जा काशत में मदाखलत बेजा न करें ? -वादी

उक्त तनकी सं. 1 ता 4 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य में शपथ पत्र गुरजन्त सिंह, गुरचरण सिंह, दर्शन सिंह, सरजीत सिंह, गिटन सिंह का पेश किया। जिन पर जिरह पूर्ण की गयी एवं दस्तावेज प्रदर्श किये गये।

बहस सुनी गयी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कभी कब्जा नहीं रहा है। परन्तु भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज है। सन 1956 से लेकर आज तक वादीगण के पूर्वज के समय से वादीगण के पूर्वजों का व उनके देहान्त उपरान्त वादीगण का कब्जा काशत लगातार शांतिपूर्व निर्बाध रूप से चला आ रहा है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 की सहमति रही है। वादीगण उपरोक्त रकबा के प्रतिकूल कब्जा धारी है तथा वादीगण का एडवर्स पोजेशन है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक एवं अधिकार नहीं रह गया है। अतः वाद वादी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाकर वादी को विवादित भूमि का टिनेन्ट घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादी पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। तनकी सं. 1 ता 4 को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-1 जमाबंदी संवत 2071-2074 चक 8 टीके खाता सं. 103 के मु.नं. 11-48-53 की कुल 3.264 है. भूमि महेन्द्रप्रताप वल्द रामदेव कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार दर्ज है। तथा प्रदर्श-2 जमाबंदी संवत 2071-2074 चक 8 टीके खाता सं. 44 के मु.नं. 51 की कुल 3.201 है. नहरी भूमि में महेन्द्रप्रताप वल्द रामदेव 186 हिस्सा संयुक्त खाता में दर्ज है। प्रदर्श 3 ता 9 में अधिकांश दस्तावेज सिंचाई विभाग से संबंधित है यथा शुद्धकार खसरा सिंचाई एवं सिंचाई कर रसीद आदि। वादी दर्शन सिंह ने जिरह में ब्यान किया है कि मैं महेन्द्रप्रताप

अधिकारी
रायसिंहनगर

जानता हूँ। महेन्द्र प्रताप सिंह जीवित हैं। जो 1-1^{1/2} वर्ष से गांव छोड़ गया है। मुझे मालूम है
महेन्द्र प्रताप ने मेरे पिता को जमीन बेचने की बात हुई थी। पैसे लेने देन का मुझे ज्ञान नहीं है,
महेन्द्र प्रताप ने सभी प्राप्त कर लिये थे। इकरारनामा हुआ हो, ऐसा मुझे ज्ञान नहीं है। मेरी
उम्र से ही भूमि पर कब्जा सन 1960 से चला आ रहा है, साक्ष्य में पानी परी आदि हैं।
वादी के विश्वास पर दावा पेश नहीं किया।" वादी गुरजन्त सिंह ने जिरह में ब्यान किया है कि "
महेन्द्र प्रताप के नाम दर्ज हैं। महेन्द्र प्रताप के पिता का नाम मुझे ज्ञान नहीं है। हमारे पास
प्रताप की 22 बीघा भूमि हैं। उक्त भूमि पर हमारा 60 वर्ष से कब्जा है। कब्जे के साक्ष्य के
हाई कोर्ट से हमारे पक्ष में हुआ फैसला पेश किया है। उक्त भूमि पर हमारा कब्जा इकरारनामा
के आधार पर है। जो 60 वर्षों से है। हमने रजिस्ट्री करवाने बावत 5-6 बार पंचायतों की जिस
कारण इतना समय व्यतीत हुआ। रजिस्ट्री करवाने के बारे में स्पष्ट इंकार कब किया मुझे जानकारी
नहीं है। अज खुद कहा कि महेन्द्रप्रताप रजिस्ट्री करवाने की बात पर टालमटोल करता है। महेन्द्र
प्रताप ने हमें कोई धमकी नहीं दी। पुनर्परीक्षण में ब्यान किया कि हाईकोर्ट क्या होती है, यह मैं नहीं
जानता। यह बात सही है कि हम कब्जे के आधार पर बैठे हैं।" वादी सरजीत सिंह ने अपनी जिरह
में ब्यान किया है कि " जो जमीन हम अपने नाम करवाना चाहते हैं वह हमने महेन्द्र प्रताप से
60-65 वर्ष पूर्व खरीदी। मेरे पिता ने महेन्द्र प्रताप से भूमि खरीदी। भूमि कितनी राशी में खरीदी
जानकारी नहीं है। 60 वर्ष से भूमि पर हमारा कब्जा है। हमारे पिताजी ने सारे पैसे दे दिए थे, इसके
उपरान्त की रजिस्ट्री नहीं करवाई। 4-5 वर्ष पहले इंकार कर दिया। महेन्द्र प्रताप के विश्वास पर न
ही इकरारनामा किया एवं ना ही दावा किया। महेन्द्र प्रताप ने उक्त भूमि बेचने की हमें कोई धमकी
नहीं दी।" वादी गिटन सिंह ने अपनी जिरह में ब्यान किया है कि "शपथ पत्र मैंने जमीन के इंतकाल
के लिए लिखाया है। भूमि का विवाद है। इसलिए शपथ पत्र न्यायालय में पेश किया है। पैसे ले
लिए लेकिन भूमि की रजिस्ट्री नहीं करवायी। पैसे महेन्द्र प्रताप ने लिए। कितनी रकम दी गयी मुझे
जानकारी नहीं है। भूमि कब खरीदी मुझे जानकारी नहीं है। भूमि मेरे पिता द्वारा महेन्द्र प्रताप से
खरीदी गई।" अतः इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा दावा एडवर्स पोजेशन के आधार
पर दायर किया गया है परन्तु वादीगण ने जिरह में भूमि उनकी जरिए इकरारनामा खरीदशुदा होना
स्वीकार किया है। अतः यदि वादीगण किसी प्रकार का अनुतोप चाहते थे तो वह
इकरारनामा/बैयनामा के आधार पर दावा पेश कर सकते थे। वादीगण द्वारा अपने दावा में किसी
प्रकार के इकरारनामा एवं बैयनामा की प्रति पेश नहीं की है। वादी द्वारा विवादित भूमि में सह
काश्तकारों को दावा में पक्षकार नहीं बनाया है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा
तारा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि निर्णय दिनांक 15.07.2015 द्वारा अनेकों प्रकरणों
का एक साथ निर्णय कर आदेश पारित किये हैं कि "No person can acquire right by adverse
possession in the lands which were resumed or are in the tenancy of the tenants as
thatedars." ऐसी स्थिति में केवल एडवर्स पोजेशन के आधार पर वादीगण को प्रतिवादी सं. 1 की
खातेदारी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं। अतः इन तनकी का निर्णय विरुद्ध
वादीगण किया जाता है।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर वादपत्र वादीगण खारिज किया जाता है। इसी आशय
की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

प्रताप
(अर्पिता सोनी)

उमरखण्ड अधिक्ती रजिस्टर
राजसिंहनगर

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर

बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

134 / 2015

एमएस : 2015 / 00642

1. दर्शन सिंह पुत्र सरवण सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. गुरुचरण सिंह पुत्र सरवण सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
3. सरजीत सिंह पुत्र गर्जा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
4. गुरजन्त पुत्र गर्जा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
5. गिटन सिंह पुत्र गर्जा सिंह जाति जटसिख निवासी 8 टीके रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

-वादीगण

बनाम

1. महेन्द्रप्रताप सिंह पुत्र रामदेव जाति ब्राहमण निवासी 8 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

-प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 88-92ए-209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: निर्णय :-

दिनांक:-08.03.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरुबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाष बिश्नोई अधिवक्ता वादीगण, राजपैरोकार पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि:-

" वादपत्र वादीगण खारिज किया जाता है। "

डिक्री आज दिनांक 08.03.2021 को जारी की गई।

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व
रायसिंहनगर